कम पानी आया या बिल्कुल नहीं आया या बहुत ही खारा पानी आया ।

नलकूपों और कुओं के निर्माण से उक्त जिलों में स्थायी तौर से पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता ।

इतने विशाल क्षेत्र में मनुष्यों एवं पशुओं को पानी पिलाने का स्थायी हल राजस्थान केनाल द्वारा ही किया जा सकता है ।

अत: केन्द्र एवं राज्य सरकार से पुर-ज़ोर निवेदन है कि राजस्थान प्रान्त के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के सैकड़ों ग्रामों में पानी पहुंचाने के लिये राजस्थान नहर के पोकरण लिफ्ट केनाल एवं लीलवा ब्रांच के गढ़रा रोड तक की स्वीकृति देकर इन नहरों से पीने के पानी की योजनाएं बनाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस थार में रेगिस्तान क्षेत्र में पीने के पानी का स्थायी हल करें ।

———

12.44 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF THE INCHEK TYRES LIMITED AND NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LIMITED (NATIONALISTION) ORDINANCE

AND

INCHEK TYRES LIMITED AND NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LIMITED (NATONALISATION) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up further discussion on the Statutory Resolution moved by Prof. Saif-Ud-Din Soz on 3rd March, 1984 and further consideration of Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited (Nationalisation) Bill moved by Shri Pattabhi Rama Rao on 3rd March, 1984.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1984 जो प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं । ये दोनों कंपनियां काफी अर्से से नुकसान में चल रही थीं । यह जो राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया है, यह यद्यपि विलंब से उठाया गया है तो भी सही कदम उठाया गया है । इसलिए मैं इस कदम का स्वागत करता हूं ।

हम यह देख रहे हैं कि प्राय: उद्योग सिक होते जा रहे हैं । इसीलिए हर अधिवेशन में अक्सर इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत होते हैं और हमें उद्योगों के राष्ट्रीकरण की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है । यह कहा जाता है कि हमारे जो प्राईवेट सेक्टर के उद्योग हैं, वे सक्सेसफुल्ली रन नहीं कर रहे हैं । वे प्राफिट में नहीं चल रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग प्राईवेट स्तर पर सक्सेफुल चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि उनको सिक इंडस्ट्रीज घोषित किया जा रहा है । इस प्रकार की स्थति है कि उन उद्योगों को बन्द कर दिया जाता है और मजदूरों के सामने अनएंप्लायमेंट की समस्या खड़ी हो जाती है राज्य सरकारों के सामने और केन्द्र सरकार के सामने यह समस्या बनी रहती है । पहले भी बबंई की टेक्सटाइल मिल्स के बारे में हमें इस तरह का निर्णय लेना पड़ा और वे एक साल तक बंद रहीं । इस प्रकार इस विषय में जो एंप्लायर्स का जो स्टेंड है उसके बारे में हमें पूरी तरह से

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

एग्जामिन करने की आवश्यकता है। उद्योगपति अपना प्राफिट तो उठा लेते हैं और लास का पूरा वजन बैंक्स पर पड़ जाता है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर पड़ जाता है, अगर उसके शेयर्स हों तो। वास्तव में यह वजन हिन्दुस्तान की जनता पर पड़ता है। यह स्थिति है। इसलिए जो राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया है वह लास्ट स्टेज पर उठाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो उद्योग प्राईवेट स्तर पर चल रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। सभी बातों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और पूरी जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए कि वाक्या में किस प्रकार से उद्योग लास में चल रहे हैं और उनके क्या कारण हैं। इन पर विस्तृत रूप से जांच हो। और इस प्रकार से जो उद्योगपति जानबूझकर उद्योगों को सिक कर रहे हों उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अगर उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे और किसी भी प्रकार का उनको नुक्सान नहीं होगा तो यह प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब मैंने इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की है कि इन्चैक टायर लिमिटेड के अंदर 25.81 करोड़ रुपए और दूसरी कंपनी नेशनल रबर मेनुफेक्चरर के अंदर 18.74 रुपए का घाटा हुआ है। इतना घाटा हो गया है। गवर्नमेंट के सामने 4500 करोड़ मजदूरों के रोजगार का प्रश्न है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन को टेकओवर किया जाए।

इन उद्योगों की बहुत सी मशीनरी आउट डेटेड हो जाती है। आउट डेटेड होने के कारण माडर्न टाइम के मुताबिक ये सूटेबल नहीं होती है। इस स्थिति मे उद्योग सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा विद्युत का जो संकट है, वह सकट भी उद्योगों को सिक बना रहा है। शार्टेज आफ पावर पर हमें पूरी तरह से सोचकर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि शार्टेज आफ पावर के कारण उद्योग असफल न हों। हमारे राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति हो रही है कि जितने भी उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं और स्थापित किए गए हैं वे भी शार्टेज आफ पावर के कारण असफल हो रहे हैं। अभी कहीं पर 50 परसेंट और कहीं पर 70 परसेंट कट हो जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों में भी इस प्रकार का कट होने से वे असफल हो जाते हैं। यह जो एक्युट पावर शार्टेज का प्रश्न है, इसके बारे में नेशनल ग्रिड बनाया जाना चाहिए। जहां-जहां भी इस प्रकार का संकट हो, उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं समझता हूं, विशेष ध्यान देना भी चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन की दृष्टि से हम जितनी तरक्की करना चाह रहे हैं, वह नहीं हो पा रही है। 1982-83 में 3.9 परसेंट इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन में वृद्धि हुई और अभी 4.9 परसेंट की वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन में घाटा हो रहा है, उसके क्या कारण हैं ? हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि सिक इन्डस्ट्रीज के लिए कौन जिम्मेदार है। इन दो कंपनीज का जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, उसका मैं

स्वागत करता हूं। यही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद घाटा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण करें और करोड़ों रुपया खर्च भी करें, उसके बावजूद भी उद्योग ठीक से न चलें तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जिन परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसका स्वागत करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): माननीय उपाध्यक्ष जी, इन-चेक टायर्स और उससे सबंधित रबड़ उत्पादन कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रीयकरण की पालिसी के बारे में अवश्य कुछ कहना चाहूंगा। प्राईवेट उद्योगों को जब हम नेशनलाइज करते हैं तो उससे पहले उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है। जैन साहब ने जो कुछ कहा, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। पूंजीपति जान-बूझकर अपनी कंपनियों की स्तिथि खराब करता है। आर्थिक रूप से जब श्रमिकों में अनरेस्ट पैदा हो जाता है, उनको तन्खवाह नहीं मिलती, तालाबन्दी कर दी जाती है तो मजबूर होकर घाटे की समस्या हमारी जनता के सिर पर थोप दी जाती है। इस पर शुरू से ही ध्यान रखना होगा। 25.81 करोड़ इन चेक टायर्स में और 18.74 करोड़ नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स में 31 मार्च 1982 तक घाटा बताया गया है। अब तो इसके आगे बढ़ गया होगा। इतना पैसा भारत की जनता को देना है। आप मारुति उद्योग की बात पहले ले लें।

एकदम उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स थे उन सब की सम्पत्ति बचा ली गई। और आज भी कार बाहर से इम्पोर्ट हो रही है, अपने आप अभी बनाई नहीं गई है।

इसी तरह से वेस्पा ऐक्स० ई० का एक भी स्कूटर आज तक नहीं बना है, जबकि उन्हें लाइसेंस दे दिया है जबकि उनके पास न कोई मकान, न दुकान और न जमीन थी। उस समय उन्हें बुक करने की इजाजत दे दी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने। लेकिन आज तक कानपुर में एक भी वेस्पा ऐक्स० ई० स्कूटर तैयार नहीं हुआ है। फिर भी बुकिंग के जरिये उनके खजाने में 1 अरब रु० जमा हो गया। तो यह जो नीतियां हैं यह अच्छी नहीं हैं।

मेरा कहना है कि जब किसी प्राइवेट फर्म, कारखाने या कंपनी की हालत खराब हो तो पहले, दूसरे साल में ही उसे देखना चाहिए। ऐसा न हो कि जब पूंजीपति बहुत ज्यादा घाटा कर दे, ऋण भी उसे दिया जाता रहे उस घाटे को पूरा करने के लिए, और बहुत ज्यादा जब ऋण हो जाए तब उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए और फिर जनता पर वह भार थोप दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि जिस चीज का भी हम राष्ट्रीयकरण करते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कारपोरेशन बनाते हैं उसके लिए बहुत लम्बी चौड़ी जमीनें ले ली जाती हैं। जो कारखाना 10, 5 बीघे या 2, 4 एकड़ या 20 एकड़ जमीन में लग सकता है उसके लिए हजारों एकड़ जमीन ली जाती है, चाहे आई०डी०पी०एल० हो भोपाल में या और कोई कारखाना हो, हमने सब जगह जा कर देखा है ऐसे सुन्दर

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

नगर बसा दिए गए हैं और अफसरों के एयर कंडीशन्ड बंगले हैं जिनमें वह रहते हैं। पूरी कालोनी को डेवलप किया जाता है जिसकी वजह से खर्चा बहुत आता है। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम राष्ट्रीयकरण करें और पब्लिक सैक्टर में उद्योग खोलें लेकिन यह जो पैसा वहां लगाया जाता है इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं आज आप से कहता हूं कि जितनी हमारी कोरपोरेशन या इंडस्ट्रीज हैं उनमें जितना पैसा लगाया गया है और जगह दी गई है उससे आधे में काम कर सकते थे बहुत उपयोगी तरीके से। मुझे कई जगह जाने का मौका मिला तो देखा कि वहां 500 या 1000 आदमी काम कर रहे हैं लेकिन नगर ऐसा बनाया गया है जिसमें 1 लाख आदमी रह सकते हैं। फिर उनके पढ़ने के लिए स्कूल, कालेज, सड़कें बनाना, बंगले बनाना यह हिंदुस्तान जैसे देश के लिए मुश्किल नहीं है, होना चाहिए, लेकिन तब जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं, रोज जनता पर टैक्स लगते हैं और दूसरी तरफ बीमार उद्योगों में पैसा चला जाता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन फिर भी इतनी सुविधायें अपने लोगों को देते हैं। और जैसा मैंने कहा 1 करोड़ रु० का उद्योग जो हम लगाते हैं, अगर वास्तविक तौर से उसका हिसाब लगाया जाए तो 50 लाख में लग सकता है। हमारा पैसा इस तरीके से राष्ट्रीयकृत उद्योगों में बहुत जा रहा है जिसकी वजह से हमारा दिवाला निकल रहा है। इसलिए इंडस्ट्रीज और नेशनलाइजेशन की पौलिसी पर फिर से गौर होना चाहिए। किसी एक्सपर्ट कमेटी को बैठाकर वर्तमान स्थिति को देख भाल कर फिर से अपनी नीति में तबदीली लानी चाहिए।

12.59 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

———

The Lok Sabha then reassembled after lunch at five : minutes past Fourteen of the Clock

14.05 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : 4 minutes late.

MR. DEPUTY SPEAKER : Thank you. I will be punctual hereafter. Don't worry.

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैनुफेक्चरर्ज लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रहे हैं। हम देख रहे है कि सदन का सत्र प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और फिर हम इस सदन में उसपर विचार करते हैं। अभी हमने गणेश फ्लोर मिल के राष्ट्रीयकरण के विधेयक को पास किया है और अब इन दो फर्मों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक हमारे सामने आया है।

राष्ट्रपति ने यह अध्यादेश 14 फरवरी, 1984 को जारी किया था, जबकि उसके आठनौ रोज बाद ही संसद का सत्र शुरू होने वाला था। पिछली बार भी मैंने

अध्यादेश जारी करने का विरोध करते हुए विधेयक का समर्थन किया था। आज भी मैं इस अध्यादेश को जारी करने का विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार को इस सदन की गरिमा को गिराने का काम नहीं करना चाहिए। यह संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। जब आठ-नौ रोज के बाद सदन का सत्र शुरू होने जा रहा था, तो राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए था। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस (इ) की सरकार को आर्डिनेंस की सरकार कहा जाए, तो कोई अनुचित नहीं होगा। यह आर्डिनेंस की सरकार संसद को विश्वास में लिए बिना अपनी मर्जी से रातों-रात फैसला करके आर्डिनेंस जारी कर देती है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वे देश के हित में होते हैं।

श्री जगपाल सिंह। अगर देश के हित की बात है, तो सरकार इस सदन में विधिवत् विधेयक ला सकती है। इसके लिए आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत नहीं है। इस सदन की गरिमा को बनाए रखने का काम केवल आपोजीशन का ही नहीं है, रूलिंग पार्टी का भी है। उनको भी आर्डिनेंस जारी करने का विरोध करना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस देश के पूंजीपतियों के साथ यहां पर सरकार के साथ बैठे हुए लोग और मन्त्रियों तक की साजिश रहती है और इस तरह से कारखानों को विफल करा करके जनता का करोड़ों रुपया बरबाद कराया जाता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यद्यपि राष्ट्रीयकरण की भावना का विरोध करता हूं। पिछले वर्षों में 25 करोड़ 81 लाख और 18 करोड़ 74 लाख यानि कुल 44 करोड़ का नुकसान उठाकर सरकार यह विधेयक यहां पर ला रही है। इस देश की जनता के पास जो पैसा आना चाहिए था, वह वहां न जाकर उन पूंजीपतियों के पास, जिनके साथ आप के लोगों की साजिश रहती है, जा रहा है। इसी कारण मैं इसका विरोध करता हूं। इस तरह से तो एक पैसा भी पूंजीपतियों को नहीं दिया जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप इंडियन पीनल कोड में संशोधन कीजिए, उसमें ऐसा प्रावधान रखिए कि अगर कोई पूंजीपति किसी फैक्टरी को खराब करेगा और सरकार उसको लेगी तो उस पूंजीपति के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये पूंजीपति पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और बैंकों का पैसा अपने कारखानों में इस्तेमाल करते हैं इसलिए आप ऐसा कानून बनाइये कि राष्ट्रीयकरण के बाद कम्पेन्सेशन के नाम पर किसी पूंजीपति को एक पैसा भी नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार पब्लिक का पैसा उनको देना देशद्रोह का काम है। आप आई०पी०सी० में अमेंडमेन्ट करिए और इस तरह के पूंजीपतियों को ब्लैकलिस्ट कीजिए तथा भविष्य में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से उनको एक भी पैसा न दिया जाए।

मैं आपका और अधिक समय न लेते हुए इसका विरोध करता हूं तथा राष्ट्रीयकरण की भावना का समर्थन करता हूं। इस प्रकार से सत्र शुरू होने से 8 दिन पहले आर्डिनेंस लाना इस देश की संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है इसलिए इसका मैं

[श्री जगपाल सिंह]

विरोध करता हूं और राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता हूं।

SHRI C.K. NAIR (Quilon) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, while extending my general support to this piece of legislation, nationalising the Incheck Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited, I have to utter a few words of caution and ask a few questions or clarifications.

These two units were started in 1963 or so and they have been sick right from the beginning. They started with a capital of Rs. 3 crores and Rs. 1.30 crores respectively. But by 1970, in a matter of 5 or 6 years or so, both have been incurring heavy losses. In one case, it was Rs. 8.9 crores and in the other case, it was Rs. 4.25 crores. The spending spree, the wasting spree, continued and the Government ultimately took over the managements in April, 1978 and February, 1978. They were going down the drain on parallel lines. I want to ask whether any check was exercised at any time by the Government or the bank people or the financial institutions who were lending money to them about the malfunctioning of these two units ? Did they examine their balance-sheets to see how their perfromance was. Till the losses amounted to Rs. 8.9 crores and Rs. 4.25 crores, nothing was done. The taking over of these two units took over in April, 1978 and February, 1978. Within 4 years, one company sustained an accumulated loss of Rs. 25.81 crores and the other company sustained an accumulated loss of Rs. 17 crores. After the take-over, the Government it self appointed the Manager or somebody who was made in-charge but they continued the spending spree, the wasting spree. In one case, they sustained a loss of Rs. 17 crores in 4 years and in the other case it was Rs. 14.5 crores.

Now, what has been the Government doing all these years ? Did they take up the responsibility at any time ? Did they ask them how things have been managed ? It is said that some problems were there. The problems cited are common to that area. One is the chronic labour trouble in West Bengal. The other is power shortage, again a chronic problem and, of course, there is news that the required raw material is to be imported. These problems could have been foreseen. But now Rs. 25.81 crores of loss is sustained in one case and Rs. 18.7 crores accumulated loss in the other case. Government has not done anything.

I would ask one or two questions. Has the labour situation in West Bengal improved ? Is it ever going to improve ? West Bengal is being ruled by a Party which calls for strikes. The Cabinet Minister ceremoniously gives a call for strike. The Chief Minister himself calls a meeting of important Ministers and inaugurates the strikes. That is the position in West Bengal. Are they going to improve the position there ? Is nationalisation going to improve the situation there ? How many times the Minister inaugurated general strikes in electricity undertakings ?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him talk.

SHRI B K. NAIR : What is the history ? Ministers ceremoniously inaugurate strikes and how are you going to improve the position ?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must have tolerance.

SHRI B. K. NAIR : Has the electricity position improved now ?

(*Interruptions*))

SHRI B.K. NAIR : They have called for strikes all the time. They enjoy strikes.

My question is are we going on the right lines. I would ask the Hon. Minister Shri Pattabhi Rama Rao, are we going on the right lines by nationalising these units. It would be better if the labour situation is improved and the power supply is improved. Has the position in regard to availability of raw materials become better now ? I do not think.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : There is more voice than the number of Members in the House.

SHRI B.K. NAIR : Therefore, as a measure of caution, we have been nationalising. It is time to examine the entire philosophy of nationalisation of sick mills. We have been taking over so many of them. In course of time, the Government will become a sanatorium of sick mills. So many crores of rupees will continue to be lost. What is the panacea ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Nationalisation is to continue in order to provide jobs to the people who become unemployed. It is one of the principles of nationalisation. As a trade unionist, I know it.

SHRI B.K. NAIR : In this case which involves about Rs. 30 crores, the number of people who got employment is 4,500.

MR. DEPUTY SPEAKER : The number is not small.

SHRI B. K. NAIR : Why not send them some money home every month, Rs. 1000/- and be satisfied by that instead of only 4,500 to be benefited at the cost of Rs. 30 crores. If it is a question of manufacturing products required by the public, I would ask one question. The tyre units are not performing cent per cent production. Their capacity is under-utilised in many cases. Some of them are going to be sick. The Appollo tyres in Kerala are already sick. Why not take them over now rather than waiting for them to collapse ?

Why not take remedial action at the proper time and before the units collapse and sink ? Why not your bank people exercise some caution while lending money ? Huge amounts of money are given as loans to these people. There should be some sort of machinery oversee, As my friend was saying, these capitalists depend on government to finance them and ultimately they make them sick deliberately and they get compensation also. They are helped in so many ways and whatever money they get they siphon it off into their pockets.

I request the Government to examine the entire philosophy of taking over sick units and do some active thinking about it.

The Finance Minister, Mr Pranab Mukherjee says in his Budget speech :

> "In order to fulfil our social commitments and protect jobs, Government had to take over a large number of sick units and sustain them through injection of fresh resources. While some of them have turned the corner, a large number of them continue to incnr losses. . . .

So nationalisation does not seem to be a cure as even after nationlisation they continue to be sick and may be more sick. Then he goes on :

> "The time has come to undertake a careful review of the performance of sick units in the public sector with a view to reducing the drain on our resources. This the Government proposes to do. Economic viability must be the principal test for the survival of an enterprise."

I will just add only one sentence,

[Shri B. K. Nair]

It is only after nationalisation or the nationalised units only are going to be examined. But before nationalisation also, you are propping all the time these units. So at the first sign of sickness in a unit, the Government should step in and do something to prevent further sickness or chuck out the people then and there. Then only they will feel the pain. Most of these units are run by business families or groups. So I would suggest that when you take over a sick unit, you also take over a healthy unit of the group so that you may be compensated in running the sick unit and you know the healthy unit in the group is built out of the money from the sick unit. Of course, this can be done only in the case of units run by business groups. But in such cases at least you take over a healthy unit just to compensate you for the losses you are going to incur or you have already incurred in the case of sick units.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। हमारे कुछ विपक्ष के मित्रों ने, जिन को इस विधेयक पर बोलने का मौका मिला है, कहीं पर तो इस बिल का स्वागत किया है और कहीं विरोध किया है। कुछ मित्रों ने कहा कि इस के राष्ट्रीयकरण का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन जिस तरह से अध्यादेश ला कर इस बिल को लाया गया है उस का विरोध करते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं—हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि जब संसद अथवा विधान-मंडल सत्र में न हो, उनका अधिवेशन न चल रहा हो, तो महामहिम राष्ट्रपति जी और राज्यपाल देश के लिए और राज्यों के लिए आर्डिनेंस जारी कर के कोई भी कानून बना सकते हैं। 14 फरवरी को पार्लियामेन्ट का अधिवेशन नहीं चल रहा था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी करके इन दो कंपनियों के, इन्चैक टायर्स और नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लि०, सरकार के कब्जे में लेने की घोषणा कर दी। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं—हमारी सरकार ने समाजवाद के सिद्धान्त को अपनाया है। इस से पहले हम यह भी देखते रहे हैं और आज भी अक्सर यह देखते हैं कि जितने भी बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के कब्जे में हैं और वहां पर जिस तरह से मजदूरों का शोषण होता है, वह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे कम्यूनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के भाई अच्छी तरह से जानते हैं।

मैं तो इस हक में हूं और इस बात में विश्वास करता हूं कि देश में जितने भी उद्योग धन्धे हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, इन सब का राष्ट्रीयकरण हो ताकि इस देश में जो बहुसंख्या में कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उन के साथ इन्साफ हो सके। प्राइवेट सेक्टर में जो कारखाने चल रहे हैं या जो कम्पनियां चल रही हैं, उनमें कमजोर वर्ग के लोगों का, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रेप्रेजेन्टेशन नाम-मात्र के लिए भी नहीं होता और उनमें केवल उन्हीं लोगों को लिया जाता है, जो मालिकों के चहेते होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस उद्योग को 6 साल पहले भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया था और तभी से ये

कंपनियां उसके नियंत्रण में चल रही हैं और उसके पहले वहां पर आए दिन शोर-शराबा, हड़ताल और आन्दोलन और इसी तरह की आपा-धापी चल रही है, जिस की वजह से मजदूरों की यूनियनों के नेताओं ने और दूसरे बहुत से लोगों ने रेप्रेजेन्टेशन सरकार को भेजे और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी अनेक डेपुटेशन मिले और इसीलिए सरकार ने सोचा कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और 14 फरवरी को महा-महीम राष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा कर दी। अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इस में यह मामला आया है। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब जबकि इन दोनों कंपनियों का राष्ट्रीय-करण हो गया है और सरकार के हाथ में ये आ गई हैं, तो यहां पर उत्पादन को बढ़ाना और मजदूरों को हर तरह की सुख-सुविधा देना, यह सरकार की जिम्मेवारी हो गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर बोर्ड में कंपनियों के मजदूरों के नुमाइन्दे लिए जाएं ताकि मजदूरों का रेप्रेजेन्टेशन हो सके। प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां चलती हैं, उनमें मजदूरों की ग्रेचुयेटी, बोनस और प्रोवीडेंट फंड में बड़ी धांधलेबाजी होती है और सरकारी नियंत्रण में जो फैक्टरी चलती है, पब्लिक सेक्टर में जो कंपनी चलती है, उन में मैं समझता हूं उनके साथ ज्यादा नाइंसाफी नहीं होती है। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा-चौड़ा न करके केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें ऐसे अच्छे अफसर भेजे जाएं, जोकि मजदूरों का ख्याल रखें और उत्पादन को भी बढ़ाएं और कंपनियों द्वारा मजदूरों के साथ जो धांधलेबाजी होती आई है और जो उन का शोषण होता आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय-करण होने के बाद, इस तरह की बातें नहीं होंगी। वहां पर 6 हजार मजदूर काम करते हैं। उन के परिवार वालों को हर तरह की सुख-सुविधा और राहत मिलेगी और उनके साथ नाइन्साफी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ टायरों की कीमतों में, जो ये कंपनियां मनमाने ढंग से वसूल करती थीं, उनमें भी कमी आएगी और सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी। मैं समझता हूं कि सरकार रेट फिक्स करके कन्ज्यूमर्स को यह उपलब्ध कराएगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुन: इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, on this Bill, many hon. Members have spoken the other day and to-day also.

I thank all the hon. Members for supporting the Bill and offering valuable suggestions. Some Members have sought clarifications. Before I deal with them, let me give general background for the nationalisation of Inchek Tyres and National Rubber Manufacturers and Salient features of the Bill.

The Inchek Tyres Limited located at Calcutta is manufcturing automobile tyres and tubes since 1963. National Rubber Manufacturers Limited, which has one unit at Tangra and another at Kalyani in West Bengal, is manufacturing various industrial rubber products like conveyor belts, V-belts, transmission belts, hoses etc. Management of these units was taken over under the Industries (Develorment and Regulation) Act, 1951 during 1977-78. A common

Board of Management was managing the undertakings. However, operational results of the undertakings continued to be unfavourable even after the take-over of management. Large investments were required for rehabilitation, replacement and modernisation of the units, which could not be provided without a decision being taken on the future disposition of the undertakings.

Various alternatives for final disposition of the undertakings were examined by the Government in light of the policy guidelines on sick industries. Nationalisation was considered as the only acceptable and feasible alternative.

A detailed examination of the viability of the undertaking by an Expert Committee has brought out that it would be possible to make the undertaking viable by renovation of the existing plants and machinery, modernisation of the production facilities in stages and by suitable change in the product-mix.

Nationalisation was considered to be in public interest taking into account the fact that the undertakings were capable of manufacturing priority industrial products and employ nearly 4500 persons. There was some delay in finalising the proposals due to doubts in regard to the size of the workforce that the undertakings could support. However based on an agreement with the workers about re-deployment of work force in different units and divisions according to the overall need of the integrated undertaking to be established and other relevant issues, a decision was finally taken to nationalise the undertaking.

The Bill provides for the acquisition of the undertakings by payment of compensation of Rs. 4.90 crores to the Companies.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): We asked how this amount was calculated. Rs. 5 crores is to be voted by us. He says, it will be disbursed. But how is it calculated ?

SHRI PATTABHI RAMA RAO : You are not a person who comes to hasty conclusions. I am coming point by point. I will meet your point presently.

MR. DEPUTY SPEAKER : How this Rs. 4.90 crore is arrived at ? That he will let you know. Let us now hear him.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I am helping him because he has come new to this.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I was once a Minister for Industry. I know the subject. You need not have any doubts about it.

A Commissioner of Payments will be appointed to disburse the compensation as per the priorities indicated in the Second Schedule of the Bill. Dues of the workers, including statutory dues, relating to the pre-takeover and post-takeover period of mangement under the IDR Act have been given the top priority.

MR. DEPUTY SPEAKER : For compersation to the workers top most priotity is given.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Second priority has been given to the principal amounts of loans obtained by the undertakings during the post-takeover management period. The Government proposes to assume undischarged liabilities in respect of loans given by Banks and financial institutions during the post-takeover period, as also the principal amounts of loans given at the behest of the Government during the pre-takeover management period and simple interest on such loans. Liabilities arising from materials supplied to the undertakings during the post takeover management period will be assumed by the Government company.

Renovation and Rehabilitation scheme will be implemented in two phases. The estimated cost of implementing the first phase is about Rs. 9.29 crores during the first 12 month. Further investments will be scrutinised before funds are released for the purpose.

On promulgation of the Ordinance the undertakings were temporaily vested in Andrew Yule and Co. Ltd. Calcutta. A new company in the name of Tyre Corporation of India Limited has since been incorporated and the undertakings have been transferred to this company on 5th March, 1984. The new company is being geared up to re-start production in the undertakings and to implement the revival and rebahilitation scheme.

Now I will come to the valuable points and suggestions made by the Hon'ble Members. I am happy to note that all the Members have supported Government decision to nationalise the undertakings. I am thankful to them. Shri T.R. Shamanna and two or three other Members have asked why the Ordinance was issued by passing the normal way of bringing up the proposals of nationalisation before the House. I have already laid on the Table of the House a statement explaining the circumstances under which promulgation of the Ordinance became necessary. I may restate, even at the cost of repeating, that the undertakings were facing a financial crisis as the banks and financial institutions found it no longer possible to finance the losses. They were reluctant even to release funds for payment of wages, salaries and other statutory dues. Moreover, any delay in acquisition would have resulted into additional unproductive burden on the public exchequer for financing payment of wages and salaries and other essential expenses without taking any step for restarting production.

Prof. Saifuddin Soz and Shri Indrajit Gupta referred to considerable dealy in nationalisation of the undertakings. They were of the view that the undertakings could have been nationalised soon after take over of management in 1977-78. I may point out that according to the then policy, the take-over of management of undertaking under the provisions of the IDR Act was not linked with its nationalisation. Immediately after management of Inchek Tyres and National Rubber Manufacturers was taken over, management and finance were provided to restore production. Efforts were thereafter called upon to make diagnostic study to establish viability and to prepare revival scheme. Consultants were appointed. IDBI and IRCI also undertook studies. When revised policy guidelines were announced in 1981, various alternatives for final disposition of the undertakings were examined. The guidelines also lay down the criteria to be satisfied before a decision can be taken in favour of nationalisation of a unit. There were some doubts whether the units could be revived in a reasonable period of time specially taking into account the excessive work force and the terms and conditions on which they were employed. A series of negotiations had to be carried out with various worker's unions of the undertakings. A tripartite agreement between the workers, management and the State Government was signed to 10-2-1984. The Ordinance was promulgated immediately thereafter on 14-2-1984.

Prof. Soz also referred to Clause 21 (2) of the Bill which requires the Commissioner of Payments to give not less than 14 days' notice through advertisement in newspapers to the creditors to file their claim. The Hon. Member suggested that the Commissioner should write to individual creditors rather than issue on advertisements calling for claim. I fully share the concern of the Hon'ble Member about the inconvenence that would be caused to the creditors. Unfortunately, however, the Commissioner of Payments will not have complete particulars about the creditors who are likely to file claim

[Shri Pattabhi Ram Rao]

with him. He can have a list of creditors and their addresses only after claims have been filed with him. He will have no means of corresponding with the creditors before collecting their names and addresses by issuing an advertisement.

Shri Mohammed Ismail has referred to non-implementation of the agreement with the workers and consequent hardship to them. I may clarify that the agreement with the workers is effective only from the date of nationalisation. As I have already stated, a new company namely Tyre Corporation of India Ltd. has just been incorporated and will now take necessary steps for implementation of the agreement. In the meanwhile, the jobs of the workers are fully secured and they are now the employees of Tyre Corporation of India Ltd. without any break in service. There may be some dislocations and delays in payment of wages and salaries for a month or two. But this cannot perhaps be helped during the transitional period. Nevertheless, all efforts would be made that there is little delay in this respect as possible.

Shri Mohammed Ismail as well as Shri Indrajit Gupta referred to general policy on takeover of sick units as well as on denotification, of taken-over units. Reference was made in this connection to a number of specific cases of sick units. It was stated that while some of the units are being closed, some other units are only partially in production. They wanted a clear enunciation of Government policy in this regard. In this connection, I would like to invite the attention of the hon. Members to the detailed policy guidelines that were announced by the Government in October, 1981. A number of questions have been answered on the floor of the House giving details of the policy guidelines.

In nutshell, the Ministries concerned in the Central Government have to take necessary responsibility for prevention and remedial action in relation to industrial sickness. The banks and financial institutions, who are in constant touch with their assisted units also monitor the health of the individual units assisted by them so as to take timely corrective action to prevent incipient sickness. They also initiate necessary corrective action for sick units on the basis of a diagnostic study. It is only when they come to the conclusion that their efforts are not likely to revive a unit, and decide to deal with their outstanding dues to any unit in accordance with the normal banking procedures, that they report the matter to the Central Government who examine whether the unit should be nationalised or whether any other alternative solution to revive the unit is available, before the banks take the legal action to recover their dues. This being the policy regarding the units managed under the IDR Act, their future disposition is to be decided and various alternatives are to be examined in detail in each case. Where none of the alternatives is feasible, there is no alternative but to discontinue Government management of such unit and allow such units to close down.

The Members will agree that where it has not been possible to revive operations of a unit inspite of managerial and financial support given by the Government, banks and financial institutions, and where the past experience suggests that basic viability of the unit is in doubt, no public purpose would be served in either continuing Government management of such units, or their nationalisation.

Shri Indrajit Gupta wanted to know the basis on which the amount of compensation has been worked out. The compensatioa is related to value of assets that are acquired. Assets are normally acquired without any liabilities. Where certain liabilities are also taken over along with assets, adjustment is naturally made in the amount of com-

pensation. In the present case, the Clause 5 (2) provides that liabilities of material supplied to the undertakings during the post-management take-over period will continue to be the liability of the Central Government or the Government company. The compensation was, therefore, determined after taking into account continuation of these liabilities.

Shri Indrajit Gupta also enquired about the manner in which the undertaking will be managed and if Government's policy in regard to workers' participation in management will be reflected in the management pattern. As I have already explained, we have set up Tyre Corporation of India Ltd. to manage these undertakings. Government want really a sound management to run the new company, and workers' support and cooperation would be a pre-requisite for revival and rehabilitation of the undertakings. Shri Gupta also wanted to know if the salaries have been paid. Hon. Members will be glad to know that the wages and salaries upto January 1984 were disbursed.

SHRI INDRAJIT GUPTA : It is March now.

MR. DEPUTY SPEAKER : The salary for February has got to be paid in March.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Do you expect workers' cooperation without their participation in management ?

SHRI PATTABHI RAMA RAO : It cannot be said now. It depends on how workers' performance turns out.

Shri N. Selvaraju raised a number of issues concerning the policy regarding tyre industry and made a number of useful suggestions. They were mostly connected with his own State. He being a DMK member, he was criticizing some of the policies of the State Government like those on sales tax etc., about which we are not concerned.

As these are not directly related to the nationalisation of Inchek. Tyres Ltd. and National Rubber Manufacturers Ltd. I will not take the time of the House by explaining the Government's view in this regard. The suggestions made by the hon. Member will, no doubt, be taken into by the Government as and when the relevant issues are taken up.

Subsequently also, some hon. Members have spoken to-day. To them also, I would say that their suggestions will be taken note of.

Having clarified various points raised by the Hon. Members, I now request Prof. Saifuddin Soz to withdraw his resolution, and beg to move that the Inchek Tyres Ltd. and National Rubber Manufacturers Ltd. Nationalization Bill, 1984 be passed.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now Prof. Soz. Please be brief.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : The Hon. Minister gave a very long, detailed and comprehensive reply to the points raised by Hon Members during the discussions that were held. But when I moved this resolution on 3rd March, I had said—and I think it must go on record—that I stood for nationalization, but that with the procedure adopted by the Government I had a strong difference of opinion. And when the Hon. Minister now spoke about certain important porints.

He mentioned about the objections raised by several Hon. Members including myself regarding no need for this Ordinance. He has mentioned in his written statement that since Parliament was not in session therefore this Ordinance was promulgated. You know that the government sought promulgation of the Ordinance on the 14th February, 1984 and the Parliament was to meet on the 23rd February, 1984.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has also explained the reasons.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : I will not say that they have brought Parliament into contempt, but I feel that the Parliament's prestige has been impaired by this action. I do not feel convinced by that argument that the Parliament was not in session. There were only 8 days left for Parliament to meet. You could wait.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : They will lose further because formerly they were under hardship.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Both these companies remained sick units. It was in 1972 that the chemical workers' federation came forward and pressed for the nationalisation ; they did not do it. So, all these years, both the companies remained under government control. During this period, the workers lived in a kind of mental anguish. For that, there can be no compensation. The Hon. Minister comes forward with a principle of compensation which is very laudable. I admit it. But they have given the Commissioner tremendous powers ; he will act only according to his whims. For instance, he gives time for filing claims, but when he has to get proof for them, he does not decide the date when he will ask for that proof ; he does not decide the date when he will advertise.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : He is given all the details. We will look into them.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : He has come forward to say that workers' claims will be settled on a priority basis. I agree that this is a very good point. But he has not risen to the occasion by the suggestions made by esteemed colleague ; Shri Indrajit Gupta and Mr. Mohammed Ismail that they should provide for the principle of compensation etc. There will be a Commissioner. They will run those companies. I do not know how. But, ultimately, the workers are going to be a casuality ; they have not invited the workers to participate in the management. The Hon. Minister is an elderly colleague. If he were a young Minister, I would have said he has made a silly remark by saying that he will watch the behaviour of the workers which will not be tolerated in a democratic country like ours.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I did not sayn that. I said, it depends upon the way in which they conduct themselves. I did not say anything about their behaviour.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : You said you will watch the workers and seek their cooperation. It is a matter of their life and death. The Hon. Minister of Labour has said that you will have their coeperation based on their participation in the management of an industry. From the very beginning, the workers should participate in the management. I stand for nationaliation. Since this is a wrong procedure, with heavy heart I say that I will not withdraw this statutory resolution.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now I shall put Statutory Resolution moved by Shri Soz to the vote of the House. The question is :

> "This House disapproves of the Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited (Nationalisation) Ordinance, 1984 (Ordinance No. 4 of 1984) promulgated by the President on the 14th February, 1984."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That the Bill to provide for acquisition and transfer of the undertakings of the Inchek Tyres Limited and the National Rubber Manufacturers Limited, with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continued

manufacture, production and distribution of tyres, tubes and other rubber goods which are essential to the needs of the economy of the country and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is :

"That Clauses 2 to 33 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 to 33 were added to the Bill.

The First Schedule, and the Second Schedule were added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause I, the Enacting Formula: the Preamble and the Title were added to the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTAY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : There are four Hon. Members. Each one will take not more than one minute. Shri Halder. Only new points may be mentioned. The points already made should not be repeated.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : The Minister in his reply has stated that there is some delay. I would like to say that there was no need for this Ordinance and I would remind you one thing, that Lok Manya Tilak said, that "what Bengal thinks today the rest of India will think tomorrow." We four opposite M.P's. of Bengal, Shri Indrajit Gupta, Shri Samar Mukherjee, Shri Mohammed Ismail and myself were pressing the Industries Minister for last four years that this company should be nationalised and the employees also, unitedly were pressing for nationalisation, and they have come forward with all cooperation for the improvement of this concern. So, the Minister should thank the employees and the officers, for they were pressing for nationalisation and he has said that for rehabilitation of the employees, it may take some time, that it would be taken up in two phases. For the first phase an amount of Rs. 9 crores. So, the participation of the workers in the management is also to be eusnred.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That the workers will fight and get it done.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : They are now forming a Tyre Corporation of India. Previously the rubber industry was monopolised by the private concerns, and the Tyre Corporation which will come into being from the 5th of March, will take care of this industry now. I want to say that the Government should follow the principle that when a public sector undertaking is producing rubber the Government should place orders on this public sector undertaking so that it can prosper and come forward.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I want to say another point. After nationalisation you should adopt a policy that you have to sanction proper funds so that the company can be modernised, I am citing one example.

[Shri Krishan Chandra Halder]

Burns Refractories Company had two units one in Raniganj and the other in Durgapur in my constituency. It has been nationalised some six or seven years ago. But they have not allocated funds for modernisation and for technological improvement. What happened is, the company has become a junk. A nationalised public sector industry should not declare a lock-out. As they have now declared a lock out in Durgapnr unit of Burns Co. Ltd and five to six hundred wokers are suffering. I would request the Hon. Minister to lift the lock out from Durgapur unit of Burns Refractries and help the workers. We have been pressing for it for a long time. He should also take steps for the modernisation of the company also.

MR. DEPUTY SPEAKER : You conclude now. Shri Harikesh Bahadur.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I must request the Government that they should take the workers in the management and the Managing Board and the Board of Chairman should be appointed after discussion with the workers and employees.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्चेक टायर्स लि० और नैशनल रबड़ मैनुफैक्चर्स लि०, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय ले कर सरकार ने अच्छा काम किया है। ऐसा करना इसलिये भी जरूरी था कि इन दोनों रबड़ उत्पादक कम्पनियों को घाटा हो रहा था। इन्चेक टायर्स लि० को 31 मार्च, 1982 तक 25 करोड़ 81 लाख रुपये और नैशनल रबड़ मैनुफैक्चर्स लि० को 18 करोड़ 74 लाख रुपये के घाटे हुए।

इन दोनों कम्पनियों को घाटा इसलिये उठाना पड़ा है कि दोनों के प्रबन्धकों ने इनकी पूंजी को या तो हजम कर लिया था या किसी दूसरे उद्योग में लगा दिया। इन बातों की ठीक प्रकार से जांच कर उन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु दु:ख है कि ऐसा करने के बजाय उनके कुप्रबन्ध, उन की लूट और टयूब एवं टायरों के उपभोक्ताओं को लूटने जैसे घृणित कार्यों के लिये उक्त दोनों कम्पनियों के मालिकों को क्रमश: 330.40 लाख और 159.64 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन के अतिरिक्त उनके मालिकों को 50-50 हजार रुपये और दिये जायेंगे। मुआवजे की राशि का जब तक भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें 4 प्रतिशत के हिसाब से सूद की राशि भी दी जायगी। मैं इस प्रावधान का सख्त विरोध कर रहा हूं।

टयूब-टायर्स बनाने वाली इन कंपनियों के अतिरिक्त फायर-स्टोन और डनलप कम्पनियां भी हैं जिनके मालिक इजारेदार पूंजीपति हैं। ये कम्पनियां भी टायरों और टयूबों के मूल्यों में वृद्धि कर आम जनता को लूट रही हैं। जब चाहा तब इन का मूल्य बढ़ा दिया जाता है जिसका बोझ साइकल चलाने वालों, बसों, स्कूटरों, टैम्पों आदि पर चढ़ने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। टायरों-टयूबों के मूल्यों की वृद्धि होने या उनके अभाव ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ बिहार के पटना जिले के फतुहा में बनी ट्रैक्टर फैक्ट्री को फायर-स्टोन और डनलप वाले टयूब-टायरों की सप्लाई नहीं करते। फलस्वरूप वहां ट्रैक्टर तैयार होने में बाधा पड़ रही है और वह कारखाना संकटों से होकर गुजर रहा है।

टायर-ट्यूब के उपभोक्ताओं को निश्चित दाम से काफी अधिक दाम देने पर भी वे वस्तुयें उन्हें नहीं मिलतीं। चोर-बाजारी का बाजार भी गर्म है। फलस्वरूप ट्रकों, बसों आदि के मालिकों में घोर असन्तोष है। अत: सरकार से मेरी मांग होगी कि वह इन बातों की ओर ध्यान भी दे ताकि आप जनता पर दिनो-दिन बढ़ रहे बोझ कम हो सकें और टायर-ट्यूब सस्ते मूल्य पर आसानी के साथ मिल सकें।

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Nationalisation of this Company is a welcome measure. But I criticise the Government on a different point that this work should have been done earlier. But they are doing it so late.

So far as workers' participation is concerned, that must be done. Government must think of workers' welfare. Therefore, I strongly demand that workers participation in the management must be there.

Import of raw rubber is a very dangerous policy. On imported rubber customs duty has also been reduced. This is going to do basic harm to the indigonous rubber growers, specially from Kerala. That is why I want that this kind of a thing must be stopped and indigenous production of rubber must be encouraged.

So far as the appointment of the Commissioner for compensation is concerned I would liko to say one thing that the Commissioner has been given wide powers. He should not have been given so much power. At the samo time, the time limit should have been specified to settle the claims which has perhaps not been done in the Bill and, therefore, I would suggest to the Hon. Minister that if he can do something in this matter, he should try to do it.

I would like to criticise the Government for giving Rs. five crores as compensation to the mill owners. This also is a very bad step which has been taken by the Government.

Finally, I would again reqquset the Hon. Minister that he must ensure the participation of workers in the management.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Sir, I have noted all that the Hon. Members have said.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

— — —

15.06 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF THE PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ORDINANCE

AND

PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY BILL

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up items No. 8 and 9. These two items are taken together regarding Statutory Resolution and also the Bill for consideration and passing by Shri Venkatasubbaiah, Dr. Subramaniam Swamy absent, Shri Suraj Bhan absent, Shri N. K. Shejwalkar.

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior) : Sir, I leave it to Mr. Jatiya to open it.

MR. DEPUTY SPEAKER : That is all right but we must call the names according to priority. Shri Indrajit Gupta absent, Shri K. A. Rajan absent, Shrimati Geeta Mukherjee absent. Now Mr. Satyanarayan Jatiya. I must